मोदी का नाम, और बैंककर्मी बदनाम

59 मिनट में लोन नहीं, दिसम्बर तक 1180 करोड़ का लोचा होगा!

ग्राउंड जीरो से विवेक की पड़ताल

मैडम, अब तो मोदी जी ने 59 मिनट में लोन देने का वादा कर दिया और आप ये पेपर और वो पेपर मांग रही हैं, ऐसे तो बात वहीँ की वहीं है। गर्दन उपर उठा कर मुंह में उछलते गुटके को सँभालते हुए लाल-लाल होंठों की मुस्कान के साथ उन्होंने अगला अन्तरा बोला, मोदी जी जो चाहे कर लें पर आप लोगों के सरकारी काम का तरीका नहीं बदलता। दिल्ली में बैंक आफ इंडिया की पंचशील ब्रांच में अधेड़ उम्र के लोन आवेदक ब्रिजलाल मौर्या ने बैंककर्मी महिला को अपने तंज से लगभग आग के शोले में रूपांतरित कर डाला।

जवाब में बैंककर्मी श्रुति (बदला हुआ नाम) ने झल्लाते हुए कहा, सर मोदी जी को क्या करना है, बस मुंह उठा के बोल देना है कुछ भी। जब चाहें नोटबंदी कर दें जब चाहें नोट बाँट दें। करना तो हमको है और गालियां भी हम बैंक वालों को खानी हैं। लोन बंट रहा है तो क्या आप पेपर नहीं देंगे अब? आप तो ऐसे मांग रहे हो जैसे मैने अपने पर्स में धरे हैं एक करोड़ और जो आये उसे निकाल कर देती फिरूं। मोदी ने । दिन पहले घोषणा की है और आप तीन चक्कर लगा चुके हैं पर पेपर नहीं ला पा रहे। सरकारी काम करने का तरीका अच्छा नहीं है सर तो मोदी जी से ही बोल दो इस तरीके को बदल दें, वैसे ही जैसे राफेल में सब बदल डाला। इतना भर कहना था और बैंक मौर्या जी के खिसियाये ठहाकों से गूँज उठा।

ब्रिजलाल मौर्या ने इस संवाददाता को बताया, क्योंकि मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को वो बहुत सपोर्ट करते हैं इसलिए प्लास्टिक बोतल क्रश करने वाली मशीन लगाना चाहते हैं और उसी के लिए लोन लेने आये हैं। अब जब मोदी जी ने 59 मिनट में लोन की सुविधा दी है तो ये बैंक वाले साले बदमाशी करेंगे ही जैसे नोटबंदी में की थी।

अखिल हांडा का 1180 करोड़ का मोदी स्ट्रोक : लोन आवेदक पहले जैसे ही हांडते फिरेंगें

32 वर्षीय श्रुति से इस विवाद के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, देखो सर मैं ज्यादा वक्त तो आपको नहीं दे सकती हूँ पर मोटा मोटी इतना जान लो कि 59 मिनट में कोई लोन नहीं मिल रहा। लोन आपको तब तक नहीं मिला मानना चाहिए जब तक कम से कम डिसबर्स ना हो जाए। 59 मिनट में तो सिर्फ आपका पंजीकरण ही हो रहा है, अब इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपको कोलैटरल नहीं देना या जो सम्बंधित पेपर हैं वे नहीं देने या और किसी तरह की रियायत है।

पास खड़े एक युवक रचित को भी इसी लोन की दरकार थी। रचित ने बताया कि यस बैंक मालचा मार्ग ब्रांच में वो लोन लेने गए थे पर उनसे वहाँ कोलेटरल माँगा गया जिससे वो संतुष्ट नहीं और इसी को क्रॉस चेक करने के लिए आज यहाँ आये हैं। हालाँकि रचित ने ये भी कहा कि उनको यस बैंक वाले कर्मी की कई बातें सही जान पड़ती हैं और इस संवाददाता को भी उस बैंक में जा कर रिपोर्ट पूरी करने की सलाह दी।

इस क्रम में यस बैंक के एक वरिष्ठ कर्मी से बैंक समय के बाद मिलना तय हुआ। अपना सही नाम नहीं छापने की शर्त पर सुमित (काल्पनिक नाम) ने बताया कि 59 मिनट में लोन देने का दावा इतना बढ़ा घपला है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने एचडब्लू न्यूज का हवाला देते हुए सारा लोचा विस्तार से बताया।

मान लो विकास नाम का एक व्यक्ति लोन लेने के लिए psbloans59minutes.com पर आवेदन भरता है। लोन के नाम पर उसे 1 लाख 48 हजार रुपये दिये जा सकते हैं ऐसा एक अधिकृत पेपर पर लिखा है जिसे "इन प्रिन्सिपल अमाउंट" कहा गया और उससे 1180 रुपये आवेदन करने के लिए चार्ज किये जाते हैं। ये 1180 रुपये किसने और क्यों लिए इसी में सारा घपला छिपा है।

सबसे पहली बात ये कि बैंक स्वत: लोन देने पर प्रोसेसिंग फीस लेता है, पर सिर्फ आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं लेता। तो बिना लोन स्वीकृत हुये ही प्रोसेसिंग का ये पैसा किसने और क्यों लिया? '59 मिनट में लोन लो' जैसी घोषणा प्रधानमंत्री ने की और लोन देंगे सरकारी बैंक तो बीच में ये पैसे "कैपिटल वर्ल्ड प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड" नामक कम्पनी क्यों ले रही है? ये कम्पनी गुजरात के नवरंगपुर, अहमदाबाद में पंजीकृत है।

"कैपिटल व्लर्ड प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड" वर्ष 2015 में अस्तित्व में आई और 30 मार्च को गुजरात के ही जिनांद शाह नामक व्यक्ति जब इसके निदेशक बने तब इसकी कोई आय नहीं थी। एक अन्य गुजराती विकास शाह अप्रैल 2016 में निदेशक सूची में शामिल हुए पर अभी भी आय शून्य है, जबकि 2017 में कुल 15680 रुपये की आय हुई। अगस्त 2018 में इस कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में अखिल हांडा शामिल होते हैं जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर के साथ मोदी के काफी करीबी रहे थे। और अब यहाँ से कम्पनी की शक्ल ताबड़तोड़ बदलने लगती है।

थोड़ी देर के लिए कंपनी की कहानी को यहीं छोड़ कर 59 मिनट लोन पर आते हैं। 20 जनवरी 2018 को सरकार 59 मिनट सर्विसेज को चलाने के लिए एक टेंडर करती है जिसमे विश्वसनीय और बेहतर ट्रैक रिकार्ड होने के साथ 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कम्पनी ही टेंडर डाल सकती थी। साथ ही डाटा मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला कम्पनी प्रोफाइल होना भी अनिवार्य था। तो फिर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कम्पनी जो पहले से भारत सरकार में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और उनका अनुभव भी बहुत है, उनको छोड़ इस नयी और बच्चा कम्पनी को कैसे ये ठेका मिला? जब कम्पनी की वार्षिक आय ही 15 हजार है तो कैसे उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया?

कम्पनी की प्रोफाइल खोलने पर कहीं भी उसके सॉफ्टवेयर डेवेलेपर होने का जिक्र नहीं है। इसका अर्थ है कि मोदी के 59 मिनट प्रोजेक्ट के लिए ही इस कम्पनी को बनाया गया है जिसे अर्थशास्त्र में क्रोनी पूंजीवाद कहते हैं। लोन लेने के लिए कम्पनी को लोन आवेदकों की सारी डीटेल्स दी जाएंगी, जैसे जीएसटी नंबर, लॉग इन आईडी पासवर्ड, इनकम टैक्स रिटर्न का लॉग इन और पासवर्ड, बैंक डिटेल्स इत्यादि। ऐसी संवेदनशील जानकारियां किसी कंपनी के पास होने के सूरतेहाल सोचा जा सकता है कि लोग कितने असुरक्षित जोन में होंगे?

अब इस उपक्रम में सिडबी को भी शामिल कर लिया गया है। सिडबी इस कंपनी में 60 प्रतिशत का हिस्सेदार है। तो सवाल ये उठता है कि फिर सिडबी खुद क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट कर रहा? लोन का आवेदन करने मात्र पर लिया जा रहा पैसा कैपिटल वर्ल्ड के पास जा रहा है और लोन हो जाने पर .3 प्रतिशत का प्रोसेसिंग चार्ज बैंक भी लेगा। अब अगला सवाल ये है कि यदि लोन नहीं हुआ तो क्या कैपिटल वर्ल्ड को मिले आवेदन वाले पैसे वापस होंगे? जवाब है, नही। दरअसल, कैपिटल वर्ल्ड की किसी गड़बड़ी पर कोई जवाबदेही तय नहीं है।

15000 की आय वाली कम्पनी 1080 रूपए प्रति आवेदक के हिसाब से लेकर कितना पैसा छापने वाली है वो भी तब जब अब तक लगभग 1 करोड़ आवेदन आ चुके हैं, अनुमान लगा लीजिये। लोन मिले न मिले पर ये कम्पनी 31 दिसम्बर तक भारत में इस कदर लूट मचाने वाली है जितना अंग्रेज 200 साल के राज में भी नहीं लूट सके थे।

59 मिनट लोन का असल सच ये है कि आपकी इनकम और जीएसटी रिटर्न को ऑनलाइन चेक कर कैपिटल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म नामक एक कम्पनी सिर्फ इतना बता देगी कि आपको कितना लोन मिल सकता है। इसे ही 'इन प्रिंसिपल अमाउंट' कहते हैं। कम्पनी वैरीफीकेशन के लिए ग्राहक से 1180 रुपए भी वसूलेगी। यह रकम पहले भी वसूली जाती थी पर अलग-अलग बैंक ब्रांच की विभिन्न एजेंन्सीयाँ ये काम करती थीं जो अब सिर्फ कैपिटल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म कम्पनी के पास चला गया है। इससे जहाँ एक तरफ रोजगार को को धक्का लगेगा वहीं निजता के अधिकार की भी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी।

जब इस स्कीम में नया कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि सब आवेदकों के पैसे पर एकाधिकार एक कम्पनी का हो जायेगा तो फिर क्या कारण है जो यह स्कीम मोदी जी के श्रीमुख से घोषित करायी गयी? इसी सवाल को सामने रख कर यदि देखा जाए और जांच कराई जाए तो इस 59 मिनट लोन के घपले की परतें रफाल की तरह धीरे धीरे खुलने लगेंगी। चौकीदार की चौकीदारी पर अंध-भरोसा न कर समझना चाहिए कि मोदी सरकार में सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। इसलिए न भेड़ बनें और न भेड़िये पर भरोसा करें।

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब कॉलेजों, युनिवर्सिटियों में भी बनेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.)। 'मजदूर मोर्चा' के पिछले अंकों में एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें ड्राइविंग लाईसेंस (लर्निंग व पक्का) बनवाने तथा उसके नवीकरण के नाम पर होने वाली सरकारी व दलालों की लूट का विवरण प्रकाशित किया गया था लगता है खट्टर सरकार के कान पर कुछ जूं तो रेंगी है। इसके चलते 15 नवम्बर को हुई कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि लर्निंग ड्राइविंग लाईसेंस बनाने का अधिकार तमाम सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, मैडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा आईटीआई के प्रिंसिपलों अथवा डायेरक्टरों को और युनिवर्सिटयों के रजिस्ट्रारों को दे दिये जायेंगे। इतना ही नहीं लर्निंग समय पूरा होने पर ड्राइविंग टैस्ट लेकर पास करने के बाद वे पक्के लाईसेंस हेतु लाइसेंसिंग अॅथोरिटी के पास भेजा करेंगे।

विदित है कि ड्राइविंग लाईसेंस युवा ही अधिक बनवाते हैं। इनमें से अधिकांश उपरोक्त किसी न किसी संस्थान में पढ़ भी रहे होते हैं। लाइसेंस बनवाने के चक्कर में इन युवाओं को अनेक बार एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटकर अपना कीमती समय तो बर्बाद करना ही पड़ता है, इसके अलावा वहां तरह-तरह से भ्रष्टाचारियों के हाथों जो लुटना पड़ता है वह अलग से। इतना ही नहीं इस नयी व्यवस्था से एसडीएम कार्यालय में ड्राइविंग लाईसेंस के लिये आने वालों को भारी भीड़ भी काफी हद तक छंट जायेगी।

पक्का लाईसैंस बनाने के नाम पर पुलिस का हवलदार जो कम्प्यूटर टैस्ट लेता है व कॉलेज का एक प्रोफेसर ज्यदा अच्छा ले सकेगा। इससे पुलिस की भी सिरदर्दी काफी हद तक घटेगी। कुल मिलाकर यह एक सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का, बशर्ते कि इसे नेक नियति से लागू किया जाये। जब दिल्ली सरकार घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस समेत अनेकों सेवायें अपने नागरिकों को प्रदान कर सकती है तो हरियाणा सरकार को इस छोटे से सुधार में कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिये।

फरीदाबाद सीपी सहित दर्जनों पुलिस अधिकारी बदले : किस लिए?

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'मजदूर मोर्चा के 21-27 अक्टूबर अंक में 'गुड़गांव-फरीदाबाद में तैनातियों की नीलामी का दौर' शीर्षक से खबर प्रकाशित की गयी थी। उसमें बताया गया था कि आरएसएस के संरक्षक चालक मोहन भागवत ने पानीपत जिले के पट्टी कल्याण का दौरा कर वहां संघ के लिए एक भवन निर्माण का आदेश दिया था इस काम का दायित्व गुड़गांव के एक संघ नेता जिंदल को सौंपा गया था। इसके लिये उन्हें मनपसंद अफसरों की तैनाती कराने की छूट दी गयी थी।

उधर फरीदाबाद में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर सीपी अमिताभ ढिल्लों से खास परेशान चल रहे थे क्योंकि उन्होंने यहां लगते ही उनकी पुलिस से सबंधित सारी दुकानदारी बंद करा दी थी। थोड़ी बहुत परेशानी तो कुछ अन्य भाजपाई नेताओं को भी हुई थी लेकिन इतनी नहीं जितनी कि गूजर जी को हुई थी। इसी परेशानी के चलते मंत्री गूजर ढिल्लों की यहां तैनाती के पहले दिन से ही उन्हें यहां से बदलवाने हेतु एड़ी-चोटी का जोर लगाये हुए थे।

लेकिन अब चुनाव सिर पर होने का हवाला देकर गूजर ने सीएम खट्टर पर दबाव बनाया कि उनके काम नहीं होंगे तो लोगों से वोट कैसे मांगेगे वे? गूजर पहले दिन से ही संजय कुमार को यहां सीपी लगवाने के लिए जोड़-तोड़ लगा रहे थे। गूजर को यह पक्का विश्वास है कि संजय कुमार के यहां सीपी लग जाने से उनकी लूट कमाई की टकसाल ठीक वैसे ही चलने लगेगी जैसे कि पूर्व सीपी हनीफकुरैशी के समय में चला करती थी। विदित है कि उस दौरान कुरैशी तो केवल नाममात्र के ही सीपी थे असल राज तो गूजर की खड़ाऊं कर रही थी।

लेकिन जानकारों का मानना है कि संजय कुमार किसी राजनेता के इशारों पर नाचने वाले अफसर नहीं है। बाकी तो समय बतायेगा उनकी कार्यशैली को देखकर।

प्रदूषण की दुकान चले-चले, भ्रष्टाचारियों की बले-बले

फ़रीदाबाद (म.मो.) शासक वर्ग की हरामखोरियों व रिश्वतखोरी की वजह से आज देश भर की जनता प्रदूषण का शिकार बनी हुई है। इसके बावजूद इसी प्रदूषण के नाम पर जनता को लूटने के और भी कई हथियार शासक वर्ग ने अपने भ्रष्ट कर्मचारियों को सौंप दिये हैं। ऐसा ही एक हथियार भवन निर्माण कार्यों पर रोक है। इस हथियार को लेकर निगमकर्मी गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे कि किसी के घर में यदि कोई छोटी-मोटी मरम्मत भी हो रही हो तो उसे पकड़ लेते हैं। चालान काटने की धमकी देकर अपनी जेब गर्म करके आगे निकल लेते हैं।

यद्यपि बीते सप्ताह वायु प्रदूषण में कुछ सुधार होने के चलते एनजीटी ने निर्माण कार्यों पर से रोक हटा ली थी, परन्तु लूट-कमाई करने वाले भ्रष्टाचारी अनभिज्ञ लोगों को कानून का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां बड़े बिल्डरों ने नियमानुसार निर्माण स्थल पर ऐसे पुख्ता प्रबंध किये हैं कि धूल-मिट्टी की तो बात ही क्या, सड़क पर चलने वाले अथवा पड़ोसी को पता भी नहीं चलता कि भीतर कोई निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों से बहस कौन करे। वे तो एक चालान काट देंगे फिर सफाई देने के लिए काटते रहो चक्कर कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे में लोग ले-देकर अपना पिंड छुड़ाना ही बेहतर समझते हैं।